



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2001/श्रावण 15, 1923

No. 209]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2001/SRAVANA 15, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2001

विषय :— चीन जनवादी गणराज्य और यूएई मूल के या वहाँ से निर्यात किए गए काचित (विट्रीफाइड) /प्रोसलेन टाइलों के भारत में आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू करना।

फा. सं. 37/1/2001-डी जी ए डी.— मैसर्स एसपीएल सिरामिक लि०, मुंडका, बहादुरगढ़, हरियाणा, मै० एच एंड आर जॉनसन इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र और मै० मुरुदेवहर सिरामिक्स लिमिटेड, हुबली ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (जिन्हें इसमें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित काचित/प्रोसलेन टाइलों के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जाँच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. विचाराधीन उत्पाद:

वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद 'पॉलिशयुक्त या बिना पॉलिश परिष्कृत बिना चमकीली टाइलें और चमकीली पोर्सलेन/सेरामिक टाइलें जो दोनों 3% से कम जलयुक्त हों (जिन्हें सामान्य तौर पर काचित टाइल्स/प्रोसलेन टाइल्स के रूप में जाना जाता है (जिसे इसमें इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) है। काचित/प्रोसलेन टाइलें चमकीली और बिना चमकीली टाइलों का उपयोग मुख्यतः फर्श तथा दीवारों के आच्छादन के लिए किया जाता है। इन टाइलों का उपयोग भवनों, घरों, होटलों, सिनेमा गृहों, हवाईपत्तनों, स्विमिंग पूलों, रेलवे स्टेशनों आदि पर किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि बिना चमकीली सभी प्रकार की टाइलों को अध्याय शीर्ष 69.07 में वर्गीकृत किया गया है। तथापि बिना चमकीली टाइलों का आयात प्रोसलेन की अन्य वस्तुओं की तरह अध्याय शीर्ष 69.14 के अन्तर्गत भी किया जाता है। इसके अलावा, चमकीली प्रोसलेन टाइलों का आयात अध्याय शीर्ष 69.14 के अन्तर्गत विभिन्न मद नामों से जैसाकि जीपी टाइल्स, प्रोसलेन टाइल्स, ग्रेस पोर्सलेन टाइल्स, प्रोसलेन विटरीफाइड टाइल्स इत्यादि से किया जा रहा है। इसके अलावा यह कहा गया है कि जिन चमकीली प्रोसलेन टाइलों का आयात अध्याय शीर्षक 69.14 के अन्तर्गत किया जा रहा है वे अध्याय शीर्षक 69.07 के तहत आयात की जा रही बिना चमकीली टाइलों के गुण, उपयोग, कार्य, वितरण प्रक्रिया आदि में स्थानापन्न हैं। याचिकाकर्ताओं ने आगे यह भी कहा है कि चमकीली प्रोसलेन टाइलों को बहुत से आयातकों द्वारा गलती से अध्याय शीर्षक 69.14 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा रहा है। उन उत्पादों का वर्गीकरण चमकीली टाइलों के रूप में अध्याय शीर्षक 69.08 के अन्तर्गत होना चाहिए। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि जिस वर्गीकरण के अन्तर्गत इनका आयात किया गया है उसकी अनदेखी करते हुए विचाराधीन उत्पाद के खिलाफ जाँच शुरू की जानी चाहिए। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और ये मौजूदा जाँच के दायरे पर किसी रूप में बाध्यकारी नहीं हैं।

3. घरेलू उद्योग

यह याचिका मै0 एसपीएल लि0, मै0 एच एंड आर जॉनसन इंडिया लि0 और मै0 गुरुदेवहर सिरामिक लि0 द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु का वर्गमीटर में कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन करते हैं इसलिए वे उपरोक्त नियमों के नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के आधार का मापदंड पूरा करते हैं।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य और यूएई हैं ।

5. समान वस्तु

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित माल, संबद्ध देशों के मूल के या वहाँ से निर्यातित माल के समान वस्तु है । इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजन से याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित माल को उपरोक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है ।

6. सामान्य मूल्य

सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के अनुबंध-1 में दिनांक 15.7.99 की अधिसूचना सं0 44/99-सी. शु. (एनटी) द्वारा और बाद में दिनांक 31 मई, 2001 की अधिसूचना सं0 28/2001 (एनटी) द्वारा संशोधन कर उसमें निम्नलिखित सिद्धांत 7 शामिल किया गया था:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित लागत के आधार पर अथवा किसी ऐसे तीसरे देश से ^{आधार पर} भारत समेत अन्य देशों के लिए कीमत के ^{आधार पर} किया जाएगा अथवा जहाँ यह संभव न हो वहाँ सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन, यदि आवश्यक हो, को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करके समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत समेत किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन संबद्ध देश के विकास स्तर और संदर्भाधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, उचित ढंग से किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसीय सूचना का विधिवत ध्यान रखा जाएगा । जहाँ उचित हो वहाँ किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में यदि कोई जांच की गई हो तो उसकी समय-सीमा का ध्यान भी रखा जाएगा । जांच संबंधी पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले

तीसरे देश के उपरोक्त चयन की सूचना अविलम्ब दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समयावधि प्रदान की जाएगी । *

इन नियमों में दिनांक 31.5.2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 28/2001(एनटी) द्वारा आगे और संशोधन किया गया है जिसके द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत 8 सम्मिलित किया गया है और इसकी टिप्पणी में चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है ।

"इस पैराग्राफ की टिप्पणी के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश शब्द से तात्पर्य ऐसे प्रत्येक देश से है जो उक्त टिप्पणी में सूचीबद्ध है और इसमें ऐसा कोई भी देश शामिल है जिसका निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारण करते हैं और जो देश लागत और कीमत निर्धारण संबंधी ढांचे के बाजार सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता है जिससे कि ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री से उक्त वस्तु के उचित मूल्य का पता चल सके । ऐसा निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या,

- (i) कच्ची सामग्रियों समेत कीमतों, लागतों और निविष्टियों, प्रौद्योगिकी एवं श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियों एवं निवेश के बारे में ऐसे देश की संबंधित फर्मों का निर्णय आपूर्ति एवं मांग को प्रदर्शित करने वाले बाजारी संकेतों के अनुरूप और इस बारे में महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप के बिना लिया जाता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत से बाजार मूल्य पर्याप्ततः प्रदर्शित होते हैं;
- (ii) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है जो पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, खासकर पारिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनियम व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के कारण आई हैं ;
- (iii) ऐसी फर्में दिवालियापन और सम्पत्ति संबंधी ऐसे कानूनों के अधीन हैं जो फर्म के प्रचालन हेतु कानूनी निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी प्रदान करते हैं; और
- (iv) विनियम दर परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है

किन्तु रूस और चीन जनवादी गणराज्य की बदलती हुई आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट करकों के बारे में लिखित में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसी ही एक अथवा अधिक फर्मों के लिए विद्यमान बाजारी दशाएं पाटनरोधी जांच के अधीन हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाय (उक्त नियमों के अनुबंध-1) पैराग्राफ 1 से 6 तक में निर्धारित सिद्धांतों का प्रयोग कर सकता है।

टिप्पणी

इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल हैं अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलरूस, चीन जनवादी गणराज्य, जार्जिया, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन, उजबेकिस्तान एवं विएतनाम। इनमें से ऐसा कोई देश जो यह प्रमाणित करना चाहता है कि वह इस पैराग्राफ में वर्णित मापदंड के अनुसार एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है तो वह सभी आवश्यक सूचना प्रदान कर सकता है जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूरा ध्यान किया जाएगा।

उपरोक्त यथासंशोधित नियमों के अनुसार, याचिकाकर्त्ताओं ने चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का दावा भारत में संबद्ध वस्तुओं के परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर किया है।

उपरोक्त नियमों के अनुसार यदि चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातक अपने निर्यातों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से होने का दावा करते हैं तो उसके लिए उपरोक्त नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य होगा।

यूआई के संबंध में सामान्य मूल्य के लिए याचिकाकर्त्ताओं ने यूआई के एक प्रमुख उत्पादक की कीमत सूची मुहैया कराई है। कीमत सूची में वितरकों के लिए कारखाना द्वार पर कीमतें दर्शाई गई हैं।

प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के लिए उसे प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में मान लिया है ।

7. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ताओं ने आंकड़ों के गौण स्रोतों अर्थात् मै0 इंटरनेशनल बिजनेस इन्फार्मेशन सर्विश, मुम्बई जिसके आंकड़े कस्टम डेली लिस्ट पर आधारित हैं के आधार पर संबद्ध देशों से निर्यात कीमत का दावा किया है । गौण स्रोत के आंकड़ों से याचिकाकर्ताओं ने मद-विवरण के आधार पर आंकड़ों को अलग किया है और विचाराधीन उत्पाद के सौदों को तय किया है । कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, निर्यातकर्ता देश में अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन, बंदरगाह पर हैंडलिंग और पत्तन प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है ।

8. पाटन मार्जिन

इस बात के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिससे इस बात का प्रथम दृष्ट्या संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंड जैसे बिक्री प्राप्ति में गिरावट, लाभप्रदता में गिरावट, कीमत में कटौती, कम क्षमता उपयोग, संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि और संबद्ध वस्तु की बिक्री से उचित कीमत न मिलने से घरेलू उद्योग को नुकसान, समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या यह बताते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

10. पाटनरोधी जांच का आरंभ

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

11. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की है ।

12 सूचना देना:

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में इस जाँच से जुड़े ज्ञात संबद्ध आयातकों को संबंधित सूचना निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से देने और अपने विचार निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

उपरोक्त नियम के 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जाँचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और ऐसे प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को भी अवसर प्रदान किया है जोकि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित ढंग से जाँच से संबंधित अभिवेदन दे सकती है।

13. समय-सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उनको अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। उल्लेखनीय है कि निर्धारित समयसीमा बढ़ाने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार रूचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय रूप दिए गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना देने से मना करती है या उचित समय के भीतर अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जाँच में बाधा डालती हैं तो प्राधिकारी, अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2001

Sub :—Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports into India of Vitrified/Porcelain Tiles originating in or exported from China PR and UAE.

F.No.37/1/2001-DGAD.—M/s SPL Ceramics Ltd., Mundka, Bahadurgarh, Haryana, M/s H&R Johnson India Ltd, Maharashtra and M/s Murudewhwar Ceramics Ltd, Hubli have filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') alleging dumping of Vitrified/Porcelain tiles originating in or exported from Peoples' Republic of China and United Arab Emirates (hereinafter referred to as subject countries) and requested for initiation of Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

2. PRODUCT UNDER CONSIDERATION:

The product under consideration in the present petition is "Unglazed tiles in polished or unpolished finish and Glazed Porcelain/Ceramic tiles both with less than 3% water absorption (commonly known as Vitrified Tiles/Porcelain tiles" (hereinafter referred to as subject goods). Vitrified/Porcelain tiles is Glazed and unglazed tiles are used primarily for coverings for floors as well as on walls. These tiles are used in buildings, homes, restaurants, cinema halls, airports, swimming pools, railway stations etc.

Petitioners have claimed that all types of unglazed tiles are classified in chapter heading 69.07. However unglazed tiles are also being imported under Chapter heading 69.14, as other articles of porcelain. In addition, glazed porcelain tiles are being imported under Chapter heading 69.14 with various descriptions like G.P. Tiles, Porcelain Tiles, Gres Porcelenato Tiles, Porcelain Vitrified Tiles, etc. It has further been stated that the Glazed Porcelain Tiles, being imported under Chapter heading 69.14 are substitutable with the unglazed tiles of Chapter Heading 69.07 in terms of properties, use, functions, distribution, channels etc. Petitioners have further submitted that Glazed Porcelain Tiles are erroneously being classified under Chapter Heading 69.14 by many importers. These products are rightly classifiable under Chapter Heading 69.08 as Glazed Tiles. Therefore petitioners have requested that the investigations be initiated against the product under consideration irrespective of the classification under which they are being imported. Customs classifications are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

3. **DOMESTIC INDUSTRY**

The petition has been filed by M/s SPL Ltd., M/s H&R Johnson India Ltd and M/s Murudewhwar Ceramic Ltd. The petitioners have claimed that they account for almost 60% of the total Indian production in terms of sq. mtrs. of the subject goods. Prima facie the petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

4. **COUNTRIES INVOLVED:**

The countries involved in the present investigation are the China PR and UAE.

5. **LIKE ARTICLE:**

The petitioners have claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' of the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules supra.

6. **NORMAL VALUE:**

Annexure 1 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 had been amended vide Notification No. 44/99-CUS(NT), dated 15-7-99 and subsequently Notification No. 28/2001(N.T.) dated 31st May, 2001 whereby the following Principle 7 had been added:-

"In case of imports from non-market economy countries, Normal Value shall be determined on the basis of the price of constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the Designated Authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

Vide Custom Notification No.28/2001(NT) dated 31.5.2001, further Principle 8 as under has also been inserted and in the Note appended thereto Peoples' Republic of China has been included in the list of non-market economy countries:

“The term “non market economy country” subject to the Note to this paragraph means every country listed in the note and includes any country which the Designated Authority determines and which does not operate on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise. While making such determination, the Designated Authority shall consider as to whether,

- (i) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in respect to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether cost of major inputs substantially reflect market values;
- (ii) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- (iii) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and
- (iv) the exchange rate conversions are carried out at the market rate;

Provided that in view of the changing economic conditions in Russia and in the Peoples' Republic of China, where it is shown on the basis of sufficient evidence in writing on the factors specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms are subject to anti-dumping investigations, the Designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 (of Annexure 1 of Rules supra) instead of the principles set out in this paragraph.

Note: For the purpose of this paragraph, the list of non-market economy countries is Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Peoples' Republic of China, Georgia, Kazakstan, North Korea, Kyrghyzstan, Mongolia, Russia, Tajikstan, Turkmeistan, Ukraine, Uzbekistan and Vietnam. Any country among them seeking to establish that it is a market economy country as per criteria enunciated in this paragraph, may provide all necessary information which shall be taken due account by the Designated Authority.”

In accordance to the Rules as amended above, the petitioners have claimed Normal Value for China PR based on the basis of Constructed Normal Value of the subject goods in India.

In terms of the aforesaid Rules it will be incumbent upon the exporters from the China PR , in case they claim their exports to be from market economy country, to provide sufficient evidence to the Designated Authority in accordance with the aforesaid Rules.

Regarding Normal Value in respect of UAE the petitioners have provided price list of one of the major producer in UAE. The price list indicates the ex-factory prices to the distributors.

The Authority has considered the same as prima facie evidence for Normal Value.

7. **EXPORT PRICE:**

The petitioners have claimed the export price from the subject countries based on the secondary data sources, i.e. M/s International Business Information Service, Mumbai whose data is based on the Customs Daily List. From the data of secondary source, the petitioners have sorted the data on the basis of description and clubbed the transactions for the product under consideration. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at the Export Price at ex-factory level

8. **DUMPING MARGIN**

There is prima facie evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

9. **INJURY AND CAUSAL LINK**

Various parameters relating to injury such as the decline in the sales realisation, decline in profitability, suppression, lower utilisation of capacity, increase in market share of imports from subject countries and losses to the Domestic Industry due to non-realisation fair and reasonable price from the sale of the subject goods, prima facie indicate collectively and cumulatively that the Domestic Industry has suffered material injury on account of dumping.

10. **INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS**

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

11. **PERIOD OF INVESTIGATION**

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st April, 2000 to 31st March, 2001.

12. **SUBMISSION OF INFORMATION**

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the

Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi – 11 00 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

13. **TIME LIMIT**

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request whatsoever shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

14. **INSPECTION OF PUBLIC FILE**

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interest party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority